दूसरे देशों में भी पार्सल की दरें दूरी के आधार पर लागू हैं। अपने देश में टेलीफोन की दरें दूरी के आधार पर निश्चित की गई हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : ऐसा कोई सुझाव अभी तक हमारे पास नहीं आया है।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या सरकार दूसरे देशों में पार्सल की दरें दूरी के आधार पर होने और अपने देश में टेलीफोन की दरें दूरी के आधार पर होने के कारण यहां पार्सल की दरें भी दूरी के आधार पर लागू करने का विचार रखती है ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : No, Sir.

Survey of Indian Resources by American Space Earth Resources Satellite

*50. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of SPACE be pleased to state :

(a) whether the Department of Atomic Energy, Electronics and Space are collaborating with American authorities for survey of Indian resources by American Space Earth Resources Satellite ; and

(b) if so, the broad outlines of the project and the extent to which India is involved in it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). The Indian Space Research Organisation is interested in the problem of Earth Resources Survey through Remote Sensing using a satellite and has had discussions with the National Aeronautics and Space Agency of the United States of America which has launched an Earth Resources Technology Satellite (ERTS) on 23rd July, 1972. The question of Indian participation in the NASA project is being studied in all its aspects.

SHRI S. C. SAMANTA : Towards the end of his statement the hon. Minister says :

> "The question of Indian participation in the NASA project is being studied in all its aspects."

Who is studying it ? Has any committee been set up ? If so, may I know its terms of reference and the names of the members of the Committee ?

SHRI K. C. PANT : A study group was set up. The names of its members are : Professor Pisharoty, convener, Ltd. Gen. H. Aggarwala, Dr. Hariharan, Dr. Kanwar, Dr. Panickker, Dr. Qureshi, Dr. Raghava Rao, Professor Ramanathan, Dr. Srinivasan and Dr. Subramaniam.

SHRI S. C. SAMANTA : On 23rd July 1972 USA has launched an Earth Resources Technology Satellite. May I know whether we will wait for the result of this launching ?

SHRI K. C. PANT : As I have said in my main reply, the satellite has been launched on the 23rd July. The question of collaborating with this programme has been under consideration. Under this programme certain pictures are received from NASA. In return, certain data has to be furnished by us. An agreement has been received from NASA of USA That is being studied to see whether the draft agreement can be accepted. That is so exactly where the matter stands now.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Agreeing in principle to enter into collaboration with such organisations, may I know whether Government explored the possibility of having collaboration with certain authorities supervised by the United Nations rather than such powers which have got different considerations, so far as our country is concerned ?

SHRI K. C. PANT : I am not quite sure which are the organisations he is referring to. This satellite programme is of NASA of USA which is largely for their domestic use. Their own departments like the Department of Agriculture, Department of Natural Resources and so on are interested in this programme. It is a new programme. It is something new in the field of space technology and they hope to derive a lot of information about their resources through this programme. The ISRO also in April 1970 had requested for copies of the pictures taken over India and neighbouring seas so that we might take advantage of this. But thereafter, as I said, the agreement has come and that is under study. Till that has been studied and a decision taken, I cannot indicate what we propose to do.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : As the Satellite has to be instrumented and launched by U.S.A, I would like to know whether you are studying any safeguards in the agreement so that there will

be no espionage equipment of military significance in the Satellite.

SHRI K. C. PANT : The agreement will no doubt take care of the security aspect.

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कारों के मूल्य

+

*51. **श्री धनशाह प्रधान :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल ही मे निर्णय के सदर्भ मे कारों के नये मूल्यो की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हा, तो उनके नये मूल्य क्या क्या है तथा मूल्यो मे वृद्धि के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) . (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हा ।

(ख) तीनो प्रकार की कारो के 1-7-1972 से लागू कारखाने से निकलते समय के नये खुदरा विक्रय मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

एम्बेसेडर	16,898 रु०
फिएट डी० या प्रीमियर प्रेजिडेंट	1100-16,117 रु०
स्टैंडर्ड हेरल्ड	16,539 रु०

प्रीमियर प्रेजिडेंट (जो पहले फिएट 1100 डी० के नाम से जानी जाती थी) के मूल्य में 171 रु० की वृद्धि हुई है, एम्बेसेडर का मूल्य 48 रु० कम हो गया है और स्टैंडर्ड हैरल्ड के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नही हुआ है। प्रीमियर प्रेजिडेंट के मूल्य मे वृद्धि पुर्जों और कच्चे माल की कीमतो मे वृद्धि, श्रमिको की मजदूरी बढ जाने और सरकारी महसूल में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है ।

श्री धनशाह प्रधान : क्या निर्णय लेने से पहले इस बात का हिसाब लगाया गया था कि इस की कीमत क्या होगी और कास्ट-एनालिसिज क्या होगा ?

(ख) मूल्य निर्धारित करते समय निर्माताओ को कितना मुनाफा दिया गया है ?

(ग) मूल्य निर्धारित करते समय क्या अन्य देशो के निर्माताओ को मिलने वाले प्रतिशत को भी ध्यान मे रखा गया है ?

(घ) ..

अध्यक्ष महोदय : एक सीधा प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य ने जो अनेको प्रश्न पूछे है उनका सम्बन्ध मूलतः इस बात से है कि किस आधार पर मोटर गाडियो की कीमत तय की गई है । इस सदन को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था और मोटर गाड़ियो के मूल्य निर्धारित करने के लिये जो सिद्धान्त तय किये थे, उन्ही सिद्धान्तो के अनुसार मोटर कारों के मूल्य तय किये गये है ।

श्री धनशाह प्रधान : साधारण जनता के इस्तेमाल मे आने वाली छोटी-सस्ती कार कब तक उपलब्ध होने की आशा है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, इस सदन मे इसके पहले भी बताया गया है कि सरकार छोटी कार बनाने का विचार नहीं कर रही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर लाइसेंस किस लिये दिया गया है ?

DR. H. P. SHARMA : Would the hon. Minister be pleased to state whether the cost structure and the question of fair price has been examined by the Bureau of Industrial